नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

2008 की लेखन याचिका No.368 (एस/एस)

नरेश चंद्र ..... याचिकाकर्ता

बनाम

जिला न्यायाधीश चंपावत और अन्र। ..... प्रतिवादी

श्री आलोक मेहरा, याचिकाकर्ता श्री D.S के वकील। पटनी, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता नं।1 श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी नं.2.

माननीय तरुण अग्रवाल, जे.

इस याचिका में, एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके लिए अधिनिर्णयन की आवश्यकता होती है ताकि जब भी जिला अदालत में नियमों के तहत भविष्य में कोई चयन किया जाए तो स्पष्टता प्राप्त की जा सके।भले ही, मौजूदा रिट याचिका में अभिवचनों की कमी है, चयन आदेशिका का रिकॉर्ड तलब किया गया था, जिसे अदालत ने पढ़ा है और इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका में अभिवचन अपर्याप्त थे, योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करना उचित समझा है।

चयन आदेशिका के अनुसार याचिकाकर्ता को 15 जून, 2002 को चंपावत के न्यायाधीश पद में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था।प्रतिवादी नं.2 को भी 25 जून, 2002 को इसी चयन आदेशिका में नियुक्त किया गया था।

नतीजन याचिकाकर्ता के पहले शामिल होने के कारण, याचिकाकर्ता को U.P के नियम 12 के तहत वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक स्थापना नियम, 1955।वर्ष 2008 में, निर्धारित कोटे के भीतर समूह 'डी' के योग्य उम्मीदवारों से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।विज्ञापन ने संकेत दिया कि समूह 'डी' उम्मीदवारों के बीच से कक्षा III पद पर 4 आरक्षित पदों को भरा जाना आवश्यक था, <आईडी1>., कक्षा IV पद, जिसमें से 3 पद उन उम्मीदवारों से भरे जाने थे जिनके पास हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र था और एक पद ऐसे उम्मीदवार से भरा जाना था जिसके पास इंटरमीडिएट पास परीक्षा प्रमाण पत्र था।

उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नं।2 और अन्य योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया।एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें कंप्यूटर संचालन में ज्ञान शामिल था।जिला न्यायाधीश ने इस उद्देश्य के लिए एक चयन समिति का गठन किया, जिसने परीक्षण का संचालन किया, जिसमें प्रतिवादी नं।2 ने बेहतर अंक प्राप्त किए।चयन समिति ने तदनुसार प्रतिवादी नं.2, जिसे नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।तदनुसार, प्रतिवादी नं।2 को चयन द्वारा तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गई थी।याचिकाकर्ता, प्रतिवादी सं. की नियुक्ति से व्यथित है।2 ने तृतीय श्रेणी के पद पर मौजूदा रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता श्री D.S के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक मेहरा को सुना। पटनी, जिला न्यायाधीश, चंपावत और श्री शोभित सहारिया के लिए विद्वान अधिवक्ता, निजी प्रतिवादी नं।2.

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, पद को भरने की कवायद पदोन्नति के माध्यम से की गई थी जैसा कि उत्तराखंड अधीनस्थ नागरिक न्यायालय मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान नियम, 2007 (इसके बाद 2007 के नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 20 के उप-नियम (2) के तहत विचार किया गया था।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दक्षता के बशर्ते वरिष्ठता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति की आवश्यकता थी।वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि 2007 के ये नियम लागू नहीं होते हैं, तो उत्तरांचल सरकारी कर्मचारी (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदंड) नियम, 2004 (इसके बाद 2004 के नियम के रूप में

संदर्भित) लागू होंगे और इसके नियम 4 में प्रावधान है कि राजपत्रित पद के लिए पदोन्नति का आधार अयोग्य की निरस्त के बशर्ते वरिष्ठता होगी और नतीजन विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता वे मानदंड हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक था, जो मौजूदा मामले में चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया था और चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के दलील के जवाब में, श्री D.S। जिला न्यायाधीश चंपावत के विद्वान अधिवक्ता पटनी ने प्रस्तुत किया कि तृतीय श्रेणी का पद एक चयन पद है जैसा कि 2007 के नियमों के नियम 3 (ए) के तहत प्रदान किया गया है और इसके नतीजन चयन योग्यता पर आधारित है जैसा कि नियमों के नियम 20 के उप-नियम (3) के तहत दिया जाना है।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 20 के उप-नियम (3) के प्रावधान को देखते हुए, जिसे उप-नियम (6) के बाद संलग्न ध्यान दें के साथ पढ़ा जाता है, एक उपयुक्तता परीक्षण आयोजित किया गया था जिसमें प्रतिवादी नं।2 ने याचिकाकर्ता से अधिक अंक प्राप्त किए।चयन समिति ने सेवा रिकॉर्ड पर भी विचार किया और उसके बाद प्रतिवादी नं.2.

श्री शोभित सहारिया, निजी प्रतिवादी नं.2 का चयन आदेशिका पर एक अलग दृष्टिकोण था और उन्होंने प्रस्तुत किया कि तृतीय श्रेणी के पद को भरने की कवायद 2007 के नियमों के नियम 20 के उप नियम (10) के तहत निर्धारित शर्त और आदेशिका के अनुसार की गई थी।श्री शोभित सहरिया के अनुसार, चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर है और 31 अगस्त, 1982 की सरकारी अधिसूचना पर भी विचार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

पार्टियों द्वारा लिए गए प्रतिद्वंद्वी रुख के आलोक में, 2007 के नियमों, 2004 के नियमों और 31 अगस्त, 1982 की सरकारी अधिसूचना के कुछ प्रावधानों का विश्लेषण करना उचित होगा।

भर्ती का स्रोत 2007 के नियमों के नियम 3 में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे यहाँ निकाला गया हैः

"3. सेवा का संवर्गःमंत्रिस्तरीय सेवा में उत्तराखंड में प्रत्येक न्यायाधीश और पारिवारिक न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग और श्रेणियां शामिल होंगीः

एस. आई. नहीं।	पद का नाम	वेतनमान	भर्ती का स्रोत
(ए)	कॉपीस्ट/जूनियर क्लर्क/सहायक लेखा क्लर्क, सहायक लाइब्रेरियन, स्टेशनरी क्लर्क, अमीन ग्रेड II, सहायक रिकॉर्ड कीपर, सहायक नजीर	रु. 3050 4590 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा या नियमित समूह 'डी' कर्मचारियों में से चयन द्वारा नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार शर्तों को पूरा करते हुए, जो ऐसे सरकारी आदेशों में निर्धारित कोटा से अधिक नहीं हैं।
(ख) (ग)	सूट क्लर्क/एग्जीक्यूशन क्लर्क, अहलमद, डिप्टी कमिश्नर। नजीर, लेखा लिपिक, सत्र लिपिक, अपील लिपिक, कैशियर, विविध।क्लर्क, मुनसरीम/रीडर्स ऑफ	Rs.4000 6000 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	श्रेणी में से पदोन्नति द्वारा (ए) तीन साल का अनुभव होना।

	सिविल जज (एस. डी.) और सिविल जज (जे. डी.)/जे. एम. , लाइब्रेरियन, अमीन ग्रेड I/डिप्टी रिकॉर्ड कीपर।		
	मुनसरीम/जिला न्यायालयों के पाठक	Rs.4500 7000 या वेतनमान को फिर से तय किया गया	श्रेणी में से पदोन्नति द्वारा (बी) तीन साल होने पर
	न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश।जिला न्यायाधीश/C.J.M/अतिरिक्त न्यायाधीश।C.J.M। , सेंट्रल नजीर, रिकॉर्ड कीपर, हेड कॉपीस्ट 2nd क्लर्क	समय-समय पर सरकार द्वारा	अनुभव
(घ)	सदर मुनसरिम	Rs.5500 9000 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	पदोन्नति या श्रेणी (ग) में से चयन द्वारा जिसने कुल मिलाकर कम से कम दस साल की सेवा दी हो।
(ई)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	Rs.6500 10,500 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	(ग) और (घ) श्रेणियों में से पदोन्नति या चयन द्वारा जिसने कम से कम दस साल की सेवा दी है।
(च)	सिविल जज की अदालतों के लिए आशुलिपिक ग्रेड I (J.D) / न्यायिक मजिस्ट्रेट/C.J.M/अतिरिक्त C.J.M./सिविल जज (S.D) / अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (S.D)	Rs.4000 6000 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा
(जी)	अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालतों में व्यक्तिगत सहायक	Rs.5500 9000 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	पांच साल का अनुभव रखने वाली श्रेणी (च) में से पदोन्नति द्वारा
(एच)	जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालतों में व्यक्तिगत सहायक	Rs.6500 10500 या सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमान	श्रेणी (जी) के बीच पदोन्नति द्वारा

दीवानी अदालतें उपखंड (ए) से (ई) में उल्लिखित श्रेणियां एक संवर्ग बनाएंगी और श्रेणियां (एफ) से (एच) दूसरी संवर्ग होंगी।22.

नियम 3 (ए) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि कॉपीस्ट/जूनियर क्लर्क/सहायक लेखा क्लर्क, सहायक लाइब्रेरियन, स्टेशनरी क्लर्क, अमीन ग्रेड II, सहायक रिकॉर्ड कीपर और सहायक नजीर के पद के लिए नियमित समूह 'डी' कर्मचारियों में से चयन द्वारा सीधी भर्ती होगी।

नियम 3 (बी) निर्धारित करता है कि सूट क्लर्क/निष्पादन क्लर्क, अहलमद, डिप्टी क्लर्क का पद। नजीर, आदि। नियम 3 (ए) में उल्लिखित ऐसी श्रेणी से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, अर्थात्, इन पदों को नियम 3 (ए) में निर्दिष्ट कॉपीस्ट/जूनियर क्लर्क, सहायक लेखा क्लर्क आदि से भरा जाएगा।

उपरोक्त के आलोक में, विज्ञापन ने स्पष्ट रूप से 2007 के नियमों के नियम 3 (ए) में निर्दिष्ट पद के लिए समूह 'डी', <आईडी1> से योग्य उम्मीदवारों से समूह 'सी' पद पर नियुक्ति का संकेत दिया।

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने पाया कि तृतीय श्रेणी के पद की भर्ती नियमित नियमित समूह 'डी' कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से होती है और यह पदोन्नति का एक सरल मामला नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर चयन के माध्यम से पदोन्नति है।

नियम 20 पदोन्नति के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है।सुविधा के लिए, 2007 के नियमों के नियम 20 को नीचे निकाला गया हैः

"20. पदोन्नतिः(1) न्यायाधीश पद या परिवार न्यायालय में उच्चतर पद परिवार न्यायालय के उस न्यायाधीश पद में लिपिकों के लिए आरक्षित होगा और उनमें से उच्चतर पदों पर पदोन्नति की जाएगी।

(2) अमीनों के मामलों को छोड़कर, दक्षता के बशर्ते वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में उल्लिखित पदों के अलावा अन्य पदों को चयन पदों के रूप में माना जाएगा, जिसमें पदोन्नति जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा के साथ योग्यता के आधार पर होगी।

(4) निम्नतम श्रेणी से अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति तब की जाएगी जब व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा उपयुक्तता परीक्षण लेने के बाद परिपत्र पत्रों, सामान्य नियमों (सिविल और आपराधिक), वित्तीय हैंडबुक का पर्याप्त ज्ञान हो।

(5) सदर मुनसरिम और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पद पदोन्नति और चयन पदों के हैं।इन पदों पर पदोन्नति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें न्यायाधीश के सभी विभागों, विशेष रूप से नजरात और लेखा में काम करने का पर्याप्त ज्ञान है।सदर मुनसरिम और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति करते समय, जिला न्यायाधीश इन पदों पर अगले निम्नतम ग्रेड में काम करने वाले व्यक्तियों की उनके द्वारा निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करेंगे और फिर योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर इन पदों पर पदोन्नति करेंगे।वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायकों के मामलों पर भी जिला न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ के पद के लिए विचार किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारी।

(6) मुख्य न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, तो सदर मुनसरिम और किसी भी न्यायाधीश के सदस्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कर सकता है बशर्ते कि ऐसे न्यायाधीश में रिक्ति मौजूद हो।

नोट-किसी व्यक्ति को अक्षमता के साथ-साथ चयन पद के लिए पदोन्नति के लिए उत्तीर्ण करने में उसके पिछले सेवा रिकॉर्ड को दिया जाएगा और वरिष्ठता की अवहेलना तभी की जानी चाहिए जब पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठों की तुलना में उत्कृष्ट योग्यता का हो।

(7) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में, द्वितीय से प्रथम श्रेणी तक अमीनों को पदोन्नति, एक नियम के रूप में, सामान्य योग्यताओं की श्रेष्ठता के आधार पर विचार करते हुए, सेवा की अवधि की परवाह किए बिना, जिला न्यायाधीश के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर की जाएगी।

(8) अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में अमीनों के पदों पर पदोन्नति या नियुक्तियां आम तौर पर उन व्यक्तियों तक ही सीमित होंगी जिनके बारे में जिला न्यायाधीश को संतुष्ट किया जाता है कि उन्हें पर्याप्त जानकारी है।

(i) हिंदी और अंग्रेजी,

(ii) अंकगणित

मापन,

(iii) (vi) (vi)

प्राथमिक भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण,

सिविल प्रक्रिया संहिता,

अमीनों के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित सामान्य (सिविल) नियमः

बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश किसी अधिकारी को ऐसी योग्यताओं से छूट दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि संबंधित अधिकारी अन्यथा नियुक्ति करने के लिए उपयुक्त है।

(9) एक बार अमीन के पद पर पदोन्नत होने के बाद एक अधिकारी, सामान्य पद में अन्य पदों पर पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, अन्य क्लर्कों पर ऐसी पदोन्नति के कारणों से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो अमीन के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले उनसे वरिष्ठ थे।

(10) निर्धारित कोटे के भीतर समूह 'डी' के योग्य उम्मीदवारों से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा समूह 'सी' के न्यूनतम वेतनमान में समय-समय पर जारी नियमों और सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।"2.

नियम 20 (2) में प्रावधान है कि दक्षता के बशर्ते वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

नियम 20 (3) में प्रावधान है कि उप-नियम (2) में उल्लिखित पदों के अलावा अन्य पदों को एक चयन पद के रूप में माना जाएगा, जिसमें पदोन्नति जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा के साथ वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता पर आधारित होगी। यह कहने के लिए कि एक चयन पद के लिए, पदोन्नति योग्यता के आधार पर होगी और वरिष्ठता को भी उचित सम्मान दिया जाएगा।उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए एक उपयुक्तता परीक्षा आयोजित की जाएगी।उप-नियम (6) के बाद संलग्न ध्यान दें इंगित करता है कि किसी उम्मीदवार की दक्षता का आकलन कैसे किया जाए, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अक्षमता के साथ-साथ चयन पद के लिए पदोन्नति के लिए उत्तीर्ण करने में, उसके पिछले सेवा रिकॉर्ड को उचित सम्मान/महत्व दिया जाएगा और उस वरिष्ठता की अवहेलना केवल तभी की जाएगी जब एक कनिष्ठ अधिकारी, जिसे पदोन्नत किया जाता है, अपने वरिष्ठों की तुलना में उत्कृष्ट योग्यता का हो।नतीजन किसी व्यक्ति को उसकी अक्षमता और वरिष्ठता के लिए उत्तीर्ण करते समय सेवा के पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा, जहां एक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठों की तुलना में उत्कृष्ट योग्यता का है, उसकी अवहेलना की जाएगी।

अन्यथा, यदि सभी चीजें योग्यता के आधार पर समान हैं, तो वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा।

नियम 20 के उप-नियम (10) में निर्धारित कोटे के भीतर समूह 'डी' के योग्य उम्मीदवारों से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान है, जो समूह 'सी' के न्यूनतम वेतनमान में समय-समय पर जारी नियमों और सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

उपरोक्त के आलोक में, नियम 20 (2), 20 (3) और 20 (10) के प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं।नियम 20 (2) तब लागू होता है जब अक्षमता के बशर्ते वरिष्ठता के अनुसार केवल पदोन्नति की आवश्यकता होती है।नियम 20 (2) नियम 3 (बी) में एक कर्मचारी के लिए उल्लिखित पद के मामले में लागू होगा, जो नियम 3 (ए) में उल्लिखित व्यक्तियों से पदोन्नति का प्रावधान करता है।मौजूदा मामले में, विज्ञापन नियम 3 (ए) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति के लिए था, जिस पर प्रतिवादी नं।2 को अंततः नियुक्त किया गया।इसलिए, 2007 के नियमों का नियम 20 (2) तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।इस संबंध में याचिकाकर्ता का दलील गलत है।

श्री D.S का दलील। पटनी भी सही नहीं है।तत्काल मामले में नियम 20 (3) लागू नहीं होता है क्योंकि न्यायालय की राय है कि तत्काल मामले में नियम 20 का उप-नियम (10) लागू होता है।

सम्बंधित पद एक चयन पद है, जिसे नियम 20 के उप-नियम (10) में बताए गए नियमों और सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार योग्यता द्वारा भरा जाना आवश्यक है।

तत्काल मामले में, विज्ञापन के अनुसार, समूह 'डी' के योग्य उम्मीदवारों से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां निर्धारित कोटे के भीतर की जानी थीं।विद्या सम्बन्धी योग्यता कम कर दी गई थी।3 पदों के लिए, उम्मीदवार के पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक था और एक पद के लिए, उम्मीदवार के पास इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र होना आवश्यक था, जबकि एक लिपिक पद के लिए, जैसा कि नियम 6 में निर्दिष्ट किया गया है, विद्या सम्बन्धी योग्यता स्नातक की डिग्री है।विज्ञापन स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि नियम 20 (10) लागू किया जाना था।परीक्षा और अंक देने की शर्तें 31 अगस्त, 1982 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार थीं।अपनाई गई प्रक्रिया 31 अगस्त, 1982 के सरकारी आदेश के अनुसार थी।यह सरकारी आदेश यह भी इंगित करता है कि उम्मीदवारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाएगी।नतीजन नियम 20 (3) के तहत निर्धारित वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले में इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने चयन समिति द्वारा घोषित परिणामों के अवलोकन से पाया कि याचिकाकर्ता नरेश चंद्र ने प्रतिवादी संख्या की तुलना में 58.5% अंक प्राप्त किए।2 जिन्होंने 70.5% अंक प्राप्त किए।

निर्दिष्ट श्रेणियों में प्राप्त अंकों का विवरण नीचे दिया गया हैः

परिणाम (मध्यवर्ती कोटा)

रोल नं.	नाम	G.K./50	वर्णनात्मक/35	गणना/05	सेवा अभिलेख/10	कुल/100
04.	बृज पाल	30.	26.5	05	09	70.5
11.	नरेश चंद्र	37	12.	1.5	08	58.5

उपरोक्त से, यह इंगित करता है कि चयन समिति ने कंप्यूटर में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर भी विचार किया और सेवा रिकॉर्ड पर भी विचार किया और पाया कि प्रतिवादी नं।2 ने याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त किए थे और तदनुसार प्रतिवादी नं।2.

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन से संकेत मिलता है कि लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 55 अंकों की आवश्यकता होती है और एक बार जब कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा कर लेता है, तो उसके बाद विचार योग्यता से वरिष्ठता में बदल जाता है।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, प्राधिकरण को याचिकाकर्ता की वरिष्ठता पर विचार करने की आवश्यकता थी, जबकि प्रतिवादी नं।2, जिस पर विचार नहीं किया गया है।

अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने B.V. सिवैया अन्य अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा रखा। बनाम।के. अडांकी बाबू अन्य अन्य, (1998) 6 उच्चतम न्यायालय के मामले 720, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य भंडारण निगम अन्य अन्य में फिर से दोहराया गया था। बनाम।जगत राम और अन्य, (2011) 3 उच्चतम न्यायालय के मामले 422, योग्यता-सह-वरिष्ठता या वरिष्ठता-सह-योग्यता के मुद्दे पर।

शिवैया के मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने योग्यता-सह-वरिष्ठता और वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है।सुविधा के लिए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 को नीचे निकाला गया हैः

"9. "योग्यता-सह-श्रेष्ठता" का सिद्धांत योग्यता और योग्यता पर अधिक जोर देता है और वरिष्ठता कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।वरिष्ठता को तभी महत्व दिया जाना चाहिए जब योग्यता और योग्यता लगभग बराबर हों।भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम 5 (2) के संदर्भ में, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा" मैथ्यू, जे. भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर ने कहा हैः(एससीसीपी। 856, पैरा 37)

"सूची में शामिल करने के लिए, सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता शासी विचार होना चाहिए और वरिष्ठता केवल एक गौण भूमिका निभानी चाहिए।

यह केवल तभी होगा जब योग्यता और उपयुक्तता मोटे तौर पर बराबर होगी कि वरिष्ठता एक निर्धारक कारक होगी, या यदि दो योग्य उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता के बीच एक मूल्यांकन करना और एक दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचना उचित रूप से संभव नहीं अपने में से, तो वरिष्ठता पैमाने को झुका देगी।

इसी तरह, बेग, जे। (जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश तब थे) ने कहा हैः(एससीसीपी। 851, पैरा 22)

"22. इस प्रकार, हम सोचते हैं कि प्रासंगिक नियमों में उपयोग किए गए शब्दों के सरल अर्थ के अनुरूप, सही दृष्टिकोण यह है कि चयन सूची में किसी स्थान के लिए प्रवेश 'या' समावेशन 'परीक्षा प्रतिस्पर्धी है और सभी योग्य उम्मीदवारों पर तुलनात्मक रूप से लागू होती है और किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों की तरह न्यूनतम नहीं होती है।चयन समिति के पास सभी योग्य उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड द्वारा प्रकट तथ्यों का आकलन करने में लागू उचित मानदंड के संदर्भ में निर्धारित योग्य उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा का एक अप्रतिबंधित विकल्प है ताकि योग्यता और केवल वरिष्ठता ही शासी कारक न हो।

10. दूसरी ओर, वरिष्ठता और योग्यता के दो सिद्धांतों के बीच, "वरिष्ठता-सह-योग्यता" का मानदंड वरिष्ठता पर अधिक जोर देता है।मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद मामले में मैसूर राज्य सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम, 1957 के नियम 4 (3) (बी) पर विचार करते हुए, जिसमें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति की आवश्यकता थी, इस न्यायालय ने कहा है कि नियम के अनुसार "पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से पद के कर्तव्यों का बर्खास्तगी करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता के बशर्ते वरिष्ठता" के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति की आवश्यकता है।

यह इंगित किया गया कि जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित है, वहां अधिकारी केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है और यदि वह उच्च पद के कर्तव्यों का बर्खास्तगी करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे पारित किया जा सकता है और उसके कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया जा सकता है।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या का सार यह है कि जब योग्यता और उपयुक्तता लगभग बराबर होती है तो वरिष्ठता निर्धारण कारक बन जाती है।तत्काल मामले में, यह सिद्धांत लागू नहीं होता है।न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता था यदि नियम 20 का उप-नियम (3) समग्र रूप से लागू होता, जिसमें यह प्रावधान है कि पदोन्नति वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता पर आधारित होगी, लेकिन जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियम 20 (10) के तहत नियमों और सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित शर्तें और प्रक्रियाएं लागू होती हैं, जो केवल यह प्रावधान करती हैं कि मेधावी उम्मीदवार को ध्यान में रखा जाएगा।वरिष्ठता पर विचार न करने के लिए एक स्पष्ट विचलन था।नतीजन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आधार बनाया निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होते हैं।

अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक कमजोर निवेदन भी किया गया था, अर्थात्, 2004 के नियम 2004 के नियमों के नियम 2 में प्रदान किए गए प्रबल प्रभाव के आधार पर 2007 के नियमों और 1982 के सरकारी आदेश पर प्रबल होंगे।

सुविधा के लिए, 2004 के नियमों के नियम 2 को नीचे निकाला गया हैः

"2. प्रमुख प्रभाव-ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक या तत्काल प्रभाव वाले आदेशों के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य सेवा नियमों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

2004 के उपरोक्त नियमों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान या उस समय लागू आदेशों के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य सेवा नियमों में निहित किसी भी विपरीत के बावजूद प्रभावी होंगे।

इन नियमों के नियम 4 में प्रावधान है कि अयोग्य की निरस्त के बशर्ते वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी।

इस प्रबल प्रभाव के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादीओं द्वारा भरोसा किए गए नियम और सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं और 2004 के नियमों का एक प्रबल प्रभाव होगा और अयोग्य की निरस्त के बशर्ते वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की आवश्यकता होगी।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत करना योग्यता से रहित है।2004 के नियम सामान्य नियम हैं और विशेष नियम नहीं हैं।

2004 के नियमों के नियम 2 से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 2004 के नियम किसी भी अन्य सेवा नियमों पर प्रभावी होंगे जो अभी लागू हैं। यह कहना कि 2004 i.e के नियमों के आने की तारीख तक मौजूद सेवा नियम। 15 जून, 2004।तत्काल मामले में, अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों के लिए विशिष्ट नियम विशेष रूप से वर्ष 2007 में 2004 के नियमों के बाद बनाए गए थे।ये किसी विशेष प्रतिष्ठान के लिए विशेष नियम हैं, जो 2004 के नियमों पर हावी होंगे।2007 के नियमों की प्रस्तावना आगे स्पष्ट करती है, अर्थात् -

"संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी मौजूदा नियमों और आदेशों के अधिक्रमण में, राज्यपाल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उत्तराखंड राज्य में सिविल न्यायालयों और परिवार न्यायालयों की मंत्रिस्तरीय स्थापना में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

2007 के नियमों की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि इस विषय पर सभी मौजूदा नियमों और आदेशों को निरस्त करते हुए, राज्यपाल उत्तराखंड राज्य में सिविल न्यायालयों और परिवार न्यायालयों की मंत्रिस्तरीय स्थापना में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

यह स्पष्ट है कि 2007 के नियम दिए गए विषय में 2004 के नियमों को हटा देते हैं।

1982 का सरकारी आदेश स्पष्ट और विशिष्ट है अर्थात् निर्धारित कोटे के भीतर समूह 'सी' से समूह 'डी' तक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए।जहाँ तक नियम 20 (10) के तहत विचार की गई स्थिति का संबंध है, ये नियम लागू होंगे, क्योंकि ये सरकारी आदेश केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं और सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हैं।

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय को रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।योग्यता से रहित होने के कारण रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

मामले की परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

श्री D.S। पटनी, अधिवक्ता को संबंधित जिला न्यायाधीश को मूल अभिलेख वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक को इस फैसले की एक प्रति उत्तराखंड के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(तरुण अग्रवाल, जे.)

30 जुलाई, 2012 रजनी